AIDWA

एडवा बुलेटिन-1

जुलाई-2020

इस अंक में

- संपादकीय
- 20 लाख करोड़ के पैकेज की पूरी हकीकत: मूल भाग खोखला है- बृंदा करात
- केरल में कोरोना से लड़ाई में महिलाओं की सेना 'पेन पाड'ने संभाल रखा है मोर्चा - सुभाषिनी अली
- कविता - गुलज़ार
- सत्ता का निर्मम दुरुपयो
- पश्चिम बंगाल मे महातूफान अमफन से भीषण तबाही - कणिनिका घोष बॉस, ईशिता मुखर्जी
- काली जानें भी अहम -सुभाषिनी अली
- लाक डाउन मे सत्ता के निर्मम दुरुपयोग के कुछ उदाहरण
- छपाक, फिल्म समीक्षा - रीना शाक्य

संपादकीय

कोरोना महामारी के संकट ने हमारे संगठन के लिए जो तमाम समस्याएँ खड़ी कर दी हैं उनमे एक है 'साम्या' के न निकालने की हमारी मजबूरी। वही मजबूरी इस 'बुलेटिन' को निकालने का कारण बना।

दुर्भाग्यवश, इस पहले बुलेटिन की शुरुआत श्रद्धांजलि अर्पित करने से करनी होगी। सबसे पहले तो हमे अपनी सेना के बहादुर अधिकारी और जवानों को याद करना होगा जिन्होंने सरहद पर अपनी जान दी है। उनके इस बलिदान को याद करते हुए हम उनके परिवार के लोगों के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं।

हम उन हजारों लोगों को याद करते हैं जिनकी जानें कोरोना की वजह से चली गयी हैं। जिन लोगों की जानें बंगाल और उड़ीशा मे आए अमफन तूफान के कारण चली गयी, उनके परिवारों के दुख को हम बांटते हैं. निश्चित रूप से हम उन तमाम महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होने अपनी काम की जगह से अकल्पनीय मुसीबते और कष्ट झेलते हुए अपने घर पहुँचने के प्रयास के दौरान अपनी जाने गंवा दी। सड़क हादसो मे, ट्रेन के पहियों के नीचे दबकर, भूख से तड़पते हुए इनकी दर्दनाक और अनावश्यक मौतें हुई हैं जिनको कभी भूलाया नहीं जा सकता।

हमारा यह पहला बुलेटिन कई तरह की काली घटाओं से घिरे वातावरण मे आपके सामने आ रहा है। एक तरफ, सीमा पर तनाव के बादल छाए हुए हैं; फिर देश भर को महामारी के बादल घेरे हुए हैं; इनके साथ साथ, आम जनता की टिमटिमाती आशा की किरणों को बेकारी, भुखमरी, बीमारी और असहनीय शारीरिक और मानसिक बेहाली की काली घटाएँ लुप्त कर रही हैं।

इन परिस्थितियों मे देश की करोड़ों महिलाओं की आवाज़ उठाने का काम कितना दुभर हो गया है। ना हम सड्कों पर उतर सकते हैं, न बड़े प्रदर्शन आयोजित कर सकते हैं। चारों तरफ, महिलाओं का काम समाप्त हो रहा है, उन्हे राशन मुहैया नहीं हो रहा है, उनके साथ होने वाली तरह तरह की हिंसा ज्यों की त्यों बरकरार है, उनके और उनके बच्चों का स्वास्थ दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है और उनके घरों के पुरुष भी बेरोजगारी की चपेट मे हैं।

आंदोलन आवश्यक है और आंदोलन के नए तरीके हमे ढूंढ़ने होंगे।

इस लॉक डाउन के दौरान *AIDWA* की तमाम इकाइयों ने राहत का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया है। हजारों परिवारों को राशन, कपड़ा, साबुन,भोजन पहुंचाने का काम किया है। यही नहीं,

तमाम ज्वलंत मुद्दों पर हमने अपने संगठन के आह्वान पर स्वतंत्र रूप से देश भर मे अपना विरोध जताया *(1* जून*)*, अन्य महिला और जनवादी संगठनो के साथ सफूरा और अन्य कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया *(3* जून*)*, करोना के खिलाफ मोर्चा लेने वाले स्वास्थ कर्मी इत्यादि के साथ अपनी एकजुटता के इजहार का प्रदर्शन हमने तमाम देशवासियों के साथ किया *(22* मार्च*)*, और सीआईटीयू के आह्वान पर श्रमिक-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ हमने भी प्रदर्शन किया *(21* अप्रैल*)*, एआईकेएस ने जब किसानों की समस्याओं के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई तो हमने उनका साथ दिया *(27* मई*)* और *16* जून को जब *CPIM* ने *4* महत्वपूर्ण मांगों को लेकर ज़बरदस्त प्रदर्शन का आह्वान किया तो हमारी हजारों महिला सदस्यों ने बढ़-चढ़ के उसमे भाग लिया।

इस संपादकीय मे हम अपनी केरल की बहनों का उल्लेख ज़रूर करेंगे। केरलकी सरकार ने कोरोना से निबटने के लिए जो अहम भूमिका निभाई वह पूरे देश के लिए मिसाल है और हमे गर्व इस बात पर अवश्य है कि केरल की स्वास्थ मंत्री, श्रीमती शैलजा टीचर, हमारी *AIDWA* की नेता भी है। राज्य के लोगों और 'मेहमान' मजदूरों को स्वास्थ लाभ पहुंचाने के साथ साथ उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करने का जो बहुत बड़ा काम हुआ, उसमे केरल की तमाम महिलाएं – स्वास्थ कर्मी, पंचायत से जुड़ी तमाम महिलाएं, आशा और आंगनवाड़ी की बहने, कुटुंबश्री के हजारों समूह मे शामिल महिलाएं – ने अभूतपूर्व साहस और ऊर्जा के साथ अपने आपको शामिल किया। इनमे लाखों महिलाएं हमारी सदस्य हैं लेकिन *AIDWA* ने अपनी स्वतंत्र पहल पर भी बड़े काम किये हैं – *20* लाख से अधिक चंदा मुख्य मंत्री कोश के लिए जमा किया, हर तरह के राहत कार्य को संगठित किया और हर ज़िले मे महिलाओं के लिए हेल्प लाइन उपलब्ध करवाए जिनके माध्यम से महिलाओं की हर तरह की सहायता की गयी।

इस बुलेटिन के माध्यम से हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमे आशा है कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमे भेजेंगे और इस बुलेटिन को अधिक मददगार और प्रासंगिक बनाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी देंगे।

सुभाषिनी अली,

उपाध्यक्ष, *AIDWA*

20 लाख करोड़ के पैकेज की पूरी हकीकत: मूल भाग खोखला है

- बृंदा कारात, AIDWA की संरक्षक और
सीपीआई(एम) की पॉलिट ब्यूरो सदस्य

जिस दिन अपने घर की ओर लौटते हुए दर्दनाक यात्रा के समय ट्रक दुर्घटनाओं में 26 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई और 30 से अधिक घायल हो गए थे,भारत के वित्त मंत्री अंतरिक्ष की यात्रा और खोज को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की बात कर रही थीं। यह विचित्र बात ही नहीं है बल्कि सत्तारूढ़ शासन की करोड़ों भारतीय नागरिकों और श्रमिकों के दर्द और पीड़ा के प्रति सम्पूर्ण अवमानना को दर्शाता है। जो श्रमिक संपत्ति के निर्माता हैं,उन्हे घर लौटने के प्रयास के दौरान सैकड़ों मील का सफर भीड़भाड़ वाली ट्रकों,बसों, और अन्य वाहनो मे तय करने और रास्ते मे कुचल जाने के लिए छोड़ दिया गया है। वित्त मंत्री के दिमाग में वे नहीं थे। उनका दिमाग अधिक ऊंचाइयों पर उड़ रहा था। मजदूरों की वास्तविकता और वित्त मंत्री के शब्दों के बीच जो विरोधाभास है,उसी से प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के चरित्र का पता चलता है – ये सब हवाई बातें हैं ।

बात बिलकुल साफ है । इस अतिरिक्त पैकेज में सीधा गरीबों को उन श्रमिकों को स्थानांतरित करने के लिए एक पैसा नहीं है जिनहोने लोक डाउन की वजह से अपनी जीविका खोई हैं। याद रहे, प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कामकाजी गरीबों के विभिन्न समूहों का उल्लेख किस तरह से किया था : गलियों में फेरी लगाने वाले,घरेलू कामगार,मछुआरे इत्यादि। जिन जिनका उन्होंने नाम लिया,वे सब कितने खुश हुए। लेकिन उन्हें क्या मिला? कर्जे का आश्वासन और वित्त मंत्री का क्रूर उपदेश कि मोदी जी की सरकार दावेदारी मे नहीं, सशक्तिकरण में विश्वास रखती है। यह कहने की जरूरत नहीं कि दावेदारी का अधिकार केवल उन कॉरपोरेट्स के लिए आरक्षित है जिनके 7.5 लाख करोड रुपये के बैंक ऋण इसलिए माफ किये जा सकते हैं क्योंकि उनकी साख मजबूत है।

क्या उन लोगों से,जिनके पास दो महीने से कोई आमदनी नहीं है और जो संभवतः उधार लेकर गुजर कर रहे हैं, और कर्जा लेने के बारे में पूछना उचित है? सीधा, एकमुश्त पैसे का हस्तांतरण यह सुनिश्चित कर सकता था कि वे जरूरत का सामान खरीद सकें और अपना काम शुरू कर सके। भारत के लगभग 40 करोड़ श्रमिकों में 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में हैं। अच्छे समय में भी इनकी आमदनी बेहद अनिश्चित होती हैं। लॉकडाउन ने उनकी जीविका को बर्बाद कर दिया। अधिकांश विपक्षी दलों के साथ-साथ,दुनिया भर के जाने-माने अर्थशास्त्रियों ने प्रस्ताव दिया है कि सरकार को अगले तीन महीनों के लिए इनके जन धन या मनरेगा के बैंक खातों में पर्याप्त मात्र मे नकद पैसे का सीधा हस्तांतरण किया जाना चाहिए। यह नैतिक रूप से तो सही है ही, यह आर्थिक समझदारी का भी सुबूत है। इससे खरीद शक्ति बढ़ेगी ,मांग पैदा होगा और अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में मदद मिलेगी । यह वास्तव में "स्थानीय मुखर है " का उदाहरण होगा, स्थानीय लोगों की आवाज मुखर होने की प्रक्रिया होगी। सरकार ने इस प्रस्ताव की अनदेखी की है।

प्रधानमंत्री ने जब 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की,उन्होने आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया था । इस पैकेज मे 20 लाख करोड़ थे ही नहीं। इसमे 8 लाख करोड़ की वह राशि थी जिसे RBI ने फरवरी और मार्च की महीनों मे अलग-अलग मदों मे अर्थ व्यवस्था मे डाला था। इसमें मार्च में घोषित 1.7 लाख करोड़ का पैकेज भी शामिल था। तो यह 20 लाख करोड़ नहीं बल्कि उसके आधी ही राशि थी। सवाल ये भी है कि इस पूरे 20 लाख करोड़ रुपये में से कितना हिस्सा सरकार सीधे तौर पर वहाँ करेगी और कितना उस "प्रोत्साहन" पैकेज मे शामिल है जिसको पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और नाबार्ड जैसी संस्थाएँ वहन करेंगी? उदाहरण के लिए,वित्त मंत्री द्वारा की गई श्रमिकों के लिए घोषणा में गरीबों को सीधे लाभ पर केवल 3,500 करोड़ का अतिरिक्त खर्च शामिल है। यह अनुमानित 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं के अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न पर खर्च होने वाली राशि है। इसके पीछे भी एक कहानी है। पहले सरकार 3 करोड़ से अधिक राशन कार्ड रद्द कर चुकी है। इनमे से ज्यादातर कार्ड-धारक वास्तव मे गरीब वर्गों के लोग थे जिन को शारीरिक तौर पर सत्यापित किये बिना ही "फर्जी" करार दे दिया गया था क्योंकि उनके विभिन्न शारीरिक निशान आधार बायोमेट्रिक मानकों से मेल नहीं खाते थे। अब उनही के बारे मे सरकार दावा कर रही है कि वह बिना राशन कार्ड वालों को मुफ्त मे खाद्यान्न देने की उदारता दिखा रही है।

एक अन्य तरीके के उपयोग से भी सरकार ने खर्च की जाने वाली राशि को बढ़ाकर दिखाया है। इस खर्च मे उस पैसे को भी शामिल किया है जिस पर उसका इनका कोई अधिकार नहीं है जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड या कॉम्पेन्सेटरी एफोरेस्टेशन फंड (CAMPA)से होने वाला खर्च। CAMPA के फंड को अपने खर्च मे जोड़कर, आदिवासियों के देखभाल के अपने दावे का ही सरकार मजाक उड़ा रही है। लेकिन इसे मंत्री जी नहीं देख पा रही हैं। भारत के आदिवासियों ने जरूर इस धोखे को पहचान लिया । पहले तो सरकार कॉर्पोरेट्स को वन भूमि के अधिग्रहण,पेड़ों की कटाई और आदिवासियों के विस्थापन की अनुमति देती है। यह सब बिना आदिवासियों की अनुमति के होता है। ऐसा करने के बाद, उनके ही खून पसीने के पैसे का उपयोग उन बागानों मे उन्हे काम देने के लिए करती है जो उनसे हड़पी गई ज़मीन पर र उगाई गई हैं!

सरकार अपनी योजनाओं और आवंटन को फिर से इस्तेमाल मे लाने से नही कतराती है। पहले जो बजट के आवंटन में शामिल था उसे ही अब कोविंद पैकेज के हिस्से के रूप में पेश किया जा रहा है। इसका उदाहरण है, मार्च के पैकेज में उल्लेखित किसानों को नकद 2,000/- हस्तांतरित करने का खर्च। वित्त मंत्री ने इस बात की सच्चाई को स्वीकार करते हुए इसके बारे मे और कुछ कहने से इंकार किया।

किसानों को विशेष तौर पर एक क्रूर झटका मिला। ऐसे समय मे जब फसलो का बहुत नुकसान हुआ है, जब खर्चे बढ़े हैं और MSP से कम पर फसल की बिक्री हो रही है, सरकार ने कर्ज़ माफी

और MSP बढ़ाने से साफ इंकार कर दिया है। जले पर नामक छिड़कते हुए, सरकार ने इस बात का दावा ठोका है कि लाक डाउन के दौरान उसने ग्रामीण श्रमिकों के लिए बहुत काम किया है। उदाहरणत: वित्त मंत्री ने इस बात का दावा किया कि लाक डाउन के दौरान mnrega के काम के दिनों मे 40-50% बढ़ौतरी हुई है। सरकारी वेब साइट इसके ठीक विपरीत यह बताता है कि पिछले साल अप्रैल के महीने की तुलना मे अबकी साल काम के दिन मे 59% और काम करने वाले परिवारों मे 46% की कमी आई है। कहावत याद आती है – आंकड़े, नालायक आंकड़े, और झूठ!

एमएसएमई (लघु उद्योग) के लिए घोषित 5.4 लाख करोड़ के पैकेज में भी, सरकार की वास्तविक अनुमानित लागत महज 25,000 करोड़ की है। जब वित्त मंत्री से पूछा गया कि इस क्षेत्र की इकाइयों का सरकार पर कितने देनदारी है तो उनके लिए जवाब देना मुश्किल था। इसके पहले, नितिन गडकरी एक साक्षात्कार में खुलासा कर चुके हैं कि MSME का पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है जो करीब करीब इस पैकेज द्वारा उसको दी जाने वाली रकम के बाराबार है।

आंकड़े देने मे सरकार इतना संकोच क्यों कर रही है? दरअसल, वह देने मे इंकार कर रही है। संवाददाता सम्मेलन में यह पूछे जाने पर कि नकदी देन कितना होगा और इसे अलग से क्यों नहीं दिया जा रहा है,वित्त सचिव ने कहा कि पूरी दुनिया का ऐसा ही चलन है। अगर यह सच भी है , अगर अन्य सरकारें पारदर्शिता में विश्वास नहीं करती हैं,तो हम एक बुरे चलन की नकल क्यों करें? वास्तविक खर्च देने की अनिच्छा इसलिए है क्योंकि उच्चतम अनुमान के अनुसार भी सरकार को महज 4 लाख करोड़ या पैकेज का 20 प्रतिशत ही खर्च करना है। यह भी कुछ ज्यादा हो सकता है। यह 8 मई को जारी किए गए बयान पर आधारित है, कि वर्ष के लिए केंद्र सरकार के उधार में 4.2 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। तो इतना ही कोविद के पैकेज मर खर्च हो सकता है। इस बात की ज़्यादा संभावना है कि इस बढ़ी हुई उधारी का उपयोग उस भारी राजस्व

की कमी को पूरा करने मे होगा जो लॉकडाउन के कारण होने वाली है। (इसका मतलब है कि कोविद राहत का पैकेज इस बढ़ी हुई उधारी के बराबर भी नहीं होगा।)

प्रेस सूचना ब्यूरो की कुछ विज्ञप्तियों से उपलब्ध ब्रेकडाउन और विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा लगाए गए अनुमानो के अनुसार, सरकार 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं करेगी। यह उस दावे से बहुत कम है कि कुल जीडीपी का 10% हिस्सा पैकेज द्वारा खर्च किया जाएगा। । यह राशि केवल 1% के आसपास की होगी। 4.2 करोड़ का उच्चतम अनुमान भी जीडीपी के 2% से थोड़ा अधिक होगा। दुनिया के हर कोविद राहत पैकेज से यह सबसे कम की है।

पूरा पैकेज राज्य सरकारों की समस्याओं को हल करने में भी विफल रहा है जो कोविद के खिलाफ लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में हैं। शर्तों के साथ उनकी उधार सीमा बढ़ाने के बारे में घोषणाएं तो की गई लेकिन उन्हे जीएसटी के मुआवजे का भुगतान करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई।

सच्चाई यह है कि पूरे पैकेज को श्रमिकों और गरीबों की मदद करने के लिए नहीं,बल्कि कॉर्पोरेट समर्थक सुधारों के सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यह प्रधान मंत्री द्वारा चार 'एल' के नए मुहावरे द्वारा समझाया गया था: लैंड , लेबर , लॉ , लिकविडिटी अर्थात्त - श्रम, भूमि, कानून और नगदी। लॉकडाउन का उपयोग राष्ट्र के आर्थिक संसाधनों पर चंद हाथों मे नियंत्रण को और ज्यादा केंद्रित करने के लिए और कामकाजी लोगों के बुनियादी अधिकारों को उलटने के लिए किया जा रहा है। नौ राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों को कमज़ोर कर दिया है, जिनमें कुछ के द्वारा काम के घंटो को 12 तक बढ़ाना शामिल है। भाजपा की अगुवाई वाली तीन सरकारों ने कई श्रम कानूनों को तीन साल के लिए निलंबित कर दिया है,जो मूल रूप से श्रमिकों को गुलामों में बदल देगा। MOEFCC वेबसाइट पर पोस्ट किए गए नए मसौदे में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन के ढांचे के कमजोर पड़ने के साथ-साथ खनन से संबंधित नियमों का उदारीकरण,वन भूमि सहित भूमि के जबरन अधिग्रहण के एक नए चरण की और संकेत है। कृषि क्षेत्र में तथाकथित सुधार किसानों को बड़े पैमाने पर कृषि व्यवसायियों द्वारा कीमतों में फेरबदल पर अधिक निर्भर बना देंगे और गारंटीशुदा MSP पर सरकारी खरीद की प्रणाली कमजोर होती जाएगी। यह आत्मनिर्भरता की एक अजीब परिभाषा है कि सरकार विदेशी क्षेत्रों में निवेश की अनुमति देने के लिए सभी क्षेत्रों को उदार बना रही है, सार्वजनिक क्षेत्र को बिक्री के लिए प्रस्तुत कर रही है जिससे भारत की आत्मनिर्भरता की धुरी ही तहस नहस हो जाएगी।

यह पैकेज एक धोखा है। जल्द ही, दंतकथा के उस बच्चे की तरह ,भारत के श्रमिक और किसान भी चिल्लाएंगे: सम्राट वस्त्रहीन है।

(यह लेख एनडीटीवी ओपिनियन में 27 मई को प्रकाशित हुआ था)

केरल में कोरोना से लड़ाई में महिलाओं की सेना 'पेन पाड'ने संभाल रखा है मोर्चा

- सुभाषिनी अली

उपाध्यक्ष, ***AIDWA***

केरल में उन्हें कहते हैं 'पेन पाड', महिलाओं की सेना। उनके हर सदस्य की तरफ़ लोग इज़्ज़त से देखते हैं, उनके योगदान से कोई इंकार नहीं करता। उस सेना की हर सैनिक भी महसूस करती है कि समाज मे उसका स्तर कुछ ऊंचा हो गया है। इस एहसास से, उसका सर भी ऊंचा हो जाता है। इस महिला सेना की हज़ारों सदस्य अलग-अलग स्तरों पर राज्य में कोरोना संकट के ख़िलाफ़ बड़ी सफलताओं को हासिल कर रही हैं। इसकी तारीफ़ राज्य में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी हो रही है।

इस सेना का सबसे अधिक जाना-पहचाना चेहरा, राज्य की स्वास्थ मंत्री, शैलजा टीचर का आज बन गया है। केरल में निपाह वायरस का प्रवेश भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। स्वास्थ्य विभाग और पूरे सरकारी तंत्र के सहयोग से उससे निबटने का जो काम किया गया था उससे तमाम अनुभव तो मिले ही, इसके साथ ही नए वायरस के प्रवेश के प्रति सावधानी भी बढ़ी। जब दिसंबर के अंत मे चीन से कोरोना के प्रवेश की ख़बर मिली, तो शैलजा टीचर ने इस बात की पुष्टि की कि यह वायरस केरल ज़रूर आएगा। एक जनवरी, 2020 को ही, उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह के नियमों का पालन करना होगा और, साथ ही, यह आश्वासन भी दिया कि उन्हें डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार और उसके साथ जुड़े तमाम संगठन उनकी सुरक्षा और सलामती बनाए रखेंगे। इस तरह की पत्रकार वार्ता रोज़ होने लगी और कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी इनमे शामिल होकर स्थिति के हर मोड़ की जानकारी जनता को देने लगे। केरल की स्वास्थ सेवाओं को और मजबूत किया गया, वह ज़रूरी सामान जो स्वास्थ कर्मियों और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था, उसको भी इकट्ठा कर लिया गया।

इस सबका परिणाम था कि जब 30 जनवरी को कोरोना का पहला मरीज चीन से केरल, अपने घर लौटा तो सरकार पूरी तरह से तैयार थी। दूसरे दिन भी मरीज़ पहुंचे और यह सिलसिला बनारहा। बड़े संकट से निबटने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार पर होती है। इसके लिए कानून और वित्तीय प्रावधान मौजूद हैं लेकिन जनवरी और फरवरी के महीने भर और मार्च के तीन हफ्ते गुज़र जाने तक, केंद्र सरकार का ध्यान कोरोना पर केन्द्रित नहीं था। दिल्ली का चुनाव, ट्रंप का स्वागत, दिल्ली में हिंसा और सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों का हटाया जाना और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की जगह भाजपा की सरकार बनाने मे केंद्र सरकार अधिक दिलचस्पी दिखा रही थी। इन कामों को अंजाम देने के लिए हवाई अड्डे खुले रहे और हवाई जहाज़ उड़ते रहे। 20 मार्च को भोपाल मे भाजपा की सरकार बन गयी और उसके 4 दिन के बाद, बिना किसी से चर्चा किये, केंद्र सरकार ने लाकडॉउन घोषित कर दिया।

निश्चित तौर पर हवाई जहाजों के आवागमन ने केरल को बहुत प्रभावित किया और जो केस बढ़ रहे थे वह अधिकतर बाहर से आने वाले लोग या उनके परिवारजन या उनसे मिलने वालों के ही थे। लेकिन, केरल की सरकार ने स्कूलों इत्यादि को 13 मार्च को ही बंद करने का काम किया, सबसे अधिक टेस्टिंग करके मरीजों का पता लगाया, उनके संपर्क मे आने वाले तमाम लोगों को ट्रैक किया और अपनी मजबूत स्वस्थ व्यवस्था से उनको लाभान्वित किया। यही नहीं, सरकार ने मार्च के महीने में ही जनता को राहत पहुँचाने के बहुत सारे कदम उठाए ताकि कोई भी भूखा या परेशान न रहे। तमाम पेंशन का 6 माह का वितरण घरों पर विधवाओं, बुज़ुर्गों इत्यादि मे किया गया; पंचायत स्तर पर आम रसोई चलाकर लोगों को खाना पहुंचाया गया और बाहर से आए हुए 'मेहमान' मज़दूरों का पूरा ख्याल रखा। इसके साथ, चेकिंग और टेस्टिंग का व्यापक अभियान

जारी रहा। यही वजह हैं की अकेले केरल मे ही कोरोना प्रभावितों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाया जा सका और, जब लॉकडाउन में ढील दी गयी और पहले ट्रेन फिर हवाई जहाज़ केरल आने लगे तो उनमें मौजूद कोरोना के मरीज़ो की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी तो सरकार और समाज दोनों ही इससे निबटने के लिए तैयार था।

यह सब केरल की पेन पाड, महिलाओं की फ़ौज, के अथक परिश्रम और निष्ठा के चलते ही हुआ। केरल की सरकार के लिए 15000 डॉक्टर और नर्स काम करते हैं। स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा के दोनों निदेशक महिलाएं हैं; 14 में से 11 ज़िला स्वास्थ अधिकारी महिलाएं हैं; कुल डॉक्टरों में भी उनकी संख्या 65:35 है। नर्स, आशा बहनें, जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर और जूनियर हेल्थ वर्कर महिलाएँ ही हैं।स्वास्थ्य सेविकाओं का यह बड़ा समूह अपने परिवार और अपने घरों को भुलाकर अपने काम में जुटा है। महिला डाक्टर अपने ज़िले को छोड़ उन ज़िलों में जहां अधिक केस हैं वहाँ कई कई दिन तक तैनात रहती हैं। कई नर्सों और स्वास्थ कर्मियों ने अपने छोटे बच्चों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया है। दूध पिलाने वाली माताओं ने अपने शिशुओं को अपने दूध से वंचित रखने का काम किया है। आशा बहनें और कुटुंबश्री (एक बड़ा स्वयंसेवी संगठन) के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ का हाल-चाल पूछती हैं और उन पर निगाह भी रखती हैं।

कुटुंबश्री केरल का एक अनोखा संगठन है जिसके बारे में कहा जाता है कि हर परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य कुटुंबश्री से जुड़ी हुई है। कुटुंबश्री की शुरुआत बचत गुटों से हुई थी और केरल की वाम सरकार ने हमेशा उनको शक्तिशाली बनाने मे पूरी मदद की है। आज वह स्वास्थ

के क्षेत्र मे तो अपना योगदान दे ही रही हैं लेकिन कई अन्य क्षेत्र भी हैं जहां वह पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए दिखाई देती हैं।जब हम केरल के स्वास्थ कर्मियों के योगदान की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि सरकार और स्वास्थ विभाग उनका भी बहुत ख्याल रखता है। उनको सुरक्षा किट और पीपीई के साथ लैस किया गया है। उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखी जाती है। इसका परिणाम यह है कि दो बीमार पड़ने वाली नर्सों का फौरन इलाज किया गया और वे ठीक हो गयी। इसके विपरीत हम पाते हैं कि दुनिया भर में और अपने देश के अन्य राज्यों मे काम करने वाली काफी मलयाली नर्सें कोरोना की लड़ाई मे शहीद हो चुकी हैं। दिल्ली के एक अस्पताल की मलयाली नर्स, जो बची नहीं, ने शिकायत की थी कि उनको एक ही पीपीई बार बार पहनना पड़ रहा है। अन्य नर्सों ने इस बात की पुष्टि भी की। कहीं भी सफाई कर्मियों को पूरा किट उपलब्ध नहीं किया जाता और उनकी भी मौतों की ख़बरें आती रहती हैं। इस मामले में भी केरल अपवाद है।

13 मार्च को ही, सरकार की घोषणा के बाद, राज्य की आंगनवाड़ी कर्मियों ने घर-घर उन बच्चों को दिन का भोजन पहुंचाने का काम किया जिनके स्कूल बंद कर दिये गए थे। इसके साथ ही, उन्होंने उनको परिवारों के लिए राशन और अन्य सामान जैसे दाल, मसाला, तेल इत्यादि के बड़े पैकेट भी पहुंचाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस ज़बरदस्त राहत कार्य को संज्ञान में लेते हुए इसकी सराहना की और अन्य राज्यों से ऐसा करने का सुझाव दिया। लेकिन किसी दूसरे राज्य के लिए ऐसा करना संभव ही नहीं हो पाया। इस योजना का लाभ 3.75 लाख आंगनवाड़ी के बच्चों को और 3 लाख गर्भवती और दूध-पिलाने वाली महिलाओं को मिल चुका है। 6.75 लाख छोटे और बड़े बच्चों को पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया जा चुका है। याद रखने की बात है कि इस काम को राज्य सरकार ने स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्रों को बंद करने के साथ ही शुरू कर दिया। पके हुए खाने और कच्चे राशन और सामान की पैकिंग और उसको पहुंचाने का काम आंगनवाड़ी कर्मी ही करते हैं और उनके खिलाफ किसी तरह की कोताही की शिकायत नहीं मिली है।पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों मे 33% आरक्षण का कानून तो है ही लेकिन केरल में यह आंकड़ा अब 60% से ऊपर पहुँच गया है। कोरोना के इस दौर मे, हर पंचायत मे आम रसोई चल रहे हैं और चारों तरफ खाना बांटा गया है। मेहमान मजदूरों के कैंपो मे भी खाना – और वह भी उनके पसंद का खाना – पहुंचाया गया है।

केरल मे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का संगठन भी बहुत मजबूत है। सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाने के अलावा वह अपने स्वतंत्र पहल पर बहुत काम कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के कोष के लिए अब तक 20 लाख रुपये जमा कर दिया है (बंगाल के तूफान ग्रस्त लोगों की मदद के लिए भी वे 1 लाख रुपए भेज चुकी हैं)। इसके अलावा, हर ज़िलें मे उनकी 'हेल्प लाइन' 24 घंटे चलती है। महिलाओं की हर तरह की शिकायत वह सुनती हैं, घरेलू हिंसा की शिकायते भी, और हस्तक्षेप करके, उनकी मदद करती हैं।

इस सब का नतीजा है कि जिस केरल में सबसे पहले कोरोना का प्रवेश हुआ था, जिस केरल में रोज़ बाहर से लोग आ रहे हैं, उस केरल मे इस महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। कुल 6 लोगों की मौत हुई है और इसके लिए भी केरल की जनता शर्मिंदगी व्यक्त करती है।अब लॉकडाउन खुल रहा है। लोग काम पर जाने लगे हैं। उनको सस्ते दरों पर अच्छा और पेट-भर भोजन उपलब्ध कराने का काम 'कुटुंबश्री कैंटीन' कर रहे हैं। यहाँ 20 रुपये में कई तरह की सब्जी, चावल, इत्यादि उनको मिल जाती है।

केरल की महिलाओं के योगदान और केरल मॉडल के उदाहरण के बारे मे कहा जा रहा है कि इसकी नकल चारों तरफ की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए लेकिन इस योगदान और इस मॉडल के पीछे केरल में वाम राजनीति का शक्तिशाली होना और सरकार का वैकल्पिक नीतियों पर चलना जिनमें सार्वजनिक स्वस्थ सेवाएं और सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत करना प्रमुख हैं। इस तरह की राजनीति के चलते, केरल की जनता में बड़ी एकता और एकजुटता का एहसास है जो उसे बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। विभाजनकारी नीतियों, बेलगाम निजीकरण और गरीब विरोधी नीतियों के प्रति समर्पित सरकारें केरल के उदाहरण की तरफ केवल देख सकती हैं, उसका अनुसरण नहीं कर सकती हैं।

(यह लेख न्यूज क्लिक हिन्दी से लिया गया है - 8 जून, 2020)

“मरेंगे तो वहीं जाकर जहां पर ज़िंदगी है”

- गुलज़ार

मोदी सरकार ने 25 मार्च,2020 को एकाएक पूरे देश मे लाक डाउन की घोषणा कर दी। न किसी से चर्चा की और न किसी को तयारी का मौका दिया। देश भर मे, अपने घरों से दूर, पूरी तरह से मालिको पर आश्रित, 8 करोड़ से अधिक परवासी मजदूरों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गयी। केवल एक केरल की सरकार थी जो इन्हे अपना मेहमान मानकर उनकी देखभाल मे जुट गयी। बाकी राज्यों मे उन्हे भूख, बीमारी, और असहनीय अपमान का सामना करना पड़ा। उनके दिमाग पर अब बस घर की याद और किसी तरह घर पहुँचने की तमन्ना छा गयी। वे घर की ओर निकली। और निकले भी। पैदल, साइकिल पर, ट्रैक्टर ट्राली पर लद कर, बसों मे बोरॉ की तरह भरकर। पुलिस की मार भी खाई और रास्ते मे भूख और प्यास के साथ साथ मौत का भी सामना हुआ। सरकार ने रेल चलाई तो उसका भी बेरहमी के साथ किराया वसूला। रास्ते भर उन्हे भूखा और प्यासा रख कर काईयो को रेल के डिब्बे मे ही मौत के घाट उतारा।

पेश है उन मजदूरों के नाम गुलजार साहब की कविता:

महामारी लगी थी
घरों को भाग लिए थे सभी मज़दूर, कारीगर.
मशीनें बंद होने लग गई थीं शहर की सारी

उन्हीं से हाथ पाओं चलते रहते थे
वर्ना ज़िन्दगी तो गाँव ही में बो के आए थे.

वो एकड़ और दो एकड़ ज़मीं, और पांच एकड़
कटाई और बुआई सब वहीं तो थी

ज्वारी, धान, मक्की, बाजरे सब.
वो बँटवारे, चचेरे और ममेरे भाइयों से
फ़साद नाले पे, परनालों पे झगड़े
लठैत अपने, कभी उनके.

वो नानी, दादी और दादू के मुक़दमे.
सगाई, शादियाँ, खलियान,
सूखा, बाढ़, हर बार आसमाँ बरसे न बरसे.
मरेंगे तो वहीं जा कर जहां पर ज़िंदगी है.
यहाँ तो जिस्म ला कर प्लग लगाए थे !
निकालें प्लग सभी ने,
'चलो अब घर चलें' – और चल दिये सब,
मरेंगे तो वहीं जा कर जहां पर ज़िंदगी है !

लाक डाउन मे सत्ता के निर्मम दुरुपयोग के कुछ उदाहरण

जिस लाक डाउन के दौरान जनता असीमित कष्ट झेल रही थी और फिर लाक डाउन समाप्त होने के बाद जब देश भर मे करोना का कहर ऐसा बरपा की खत्म होने का नाम नही ले रही है, इस पूरे दौर का केंद्र सरकार ने अपने घोर प्रजातन्त्र-विरोधी, सांप्रदायिक अजेंडे को ही आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है।

'दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक साजिश की थ्योरी गढ़ी है जिसके माध्यम से CAA का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को फरवरी के आखिर मे उत्तर-पूर्वी दिल्ली मे हुए सांप्रदायिक हिंसा के साथ जोड़ा जा रहा है। अमित शाह के गृह मंत्रालय की सरपरस्ती मे जिस वस्तिविक साजिश को रचा गया है उसका खुलासा गिरफ्तारियों, मुक़द्दमे और दर्ज किए गए चार्ज शीट करते हैं .... अभियोग पक्ष (प्रसिक्यूशन) की मंशा साफ है – CAA का विरोध सांप्रदायिक हिंसा को नियोजित करने और भड़काने का पर्दा था'। *(10* जून के 'पीपल्स डेमोक्रसी' की समपादकीय*)*

आरोपियों और हर्ष मंदार जैसे मानव अधिकार कार्यकर्ता पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप लगाया गया है जबकि कपिल मिश्रा जिनका 23 फरवरी का भाषण जो पुलिस के DCP की मौजूदगी मे दिया गया था, बहुत ही उत्तेजनात्मक है, के वीरुध FIR तक नही दर्ज की गयी है। दिल्ली पुलिस के एक-तरफा व्यवहार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी टिप्पणी की है की 'केस डायरी एक परेशान करने वाले तथ्य को उजागर करता है। लगता है की जांच के निशाने पर एक ही मकसद है।'

तमाम छात्रों और कार्यकर्त्ताओं, के खिलाफ UAPA के अंतर्गत केस दर्ज किए गए हैं ताकि उन्हे जमानत से वंचित रखा जाये। इनमे JNU के शरजील इस्लाम, JNU के पूर्व छत्र, उम्र खालिद, जामिया को-अर्डिनेशन कमेटी के सफूरा जरगार (जो गर्भवती हैं), मीरान हैदर, शिफा उर रेहमान, और सामाजिक कार्यकर्त्ता, इशरत जहां शामिल हैं। सरकार की इस बदनीयती का पर्दाफ़ाश तब हुआ JNU की छात्राएँ और 'पिंजरा तोड़' संगठन की कार्यकर्त्ता, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता की बेल याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय के सामने हो रही थी। जैसे ही उनकी जमानत मंजूर हुई, क्राइम ब्रांच ने हस्तक्षेप करके उनके खिलाफ UAPA मे मुक़द्दमा दर्ज कर डाला और वे जेल से नहीं छूटीं।

गृह मंत्रालय की माने तो CAA का विरोध करना अपने आप मे आतंकवादी, देश द्रोही गतिविधि है।

याद रहे की भीमा कोरेगांव मामले मे इसी तरह से सुधा भारद्वाज, आनंद टेलटुंबड़े, गौतम नवलखा इत्यादि को फंसा कर अब UAPA के ही अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। उनके

खिलाफ किसी तरह का कोई सुबूत नहीं है। उनका अकेला अपराध यह है की उन्होने सत्तासीनों का जमकर विरोध किया है।

जनवाद पर इन हमलों को नज़रअंदाज़ नही किया जा सकता है। ऐसा करना बहुत ही महंगा पड़ेगा। जनवादी आंदोलन के साथ जुड़े हम तमाम लोगों का इन हरकतों का विरोध करना फर्ज़ बनता है।

विभिन्न महिला संगठनो के साथ AIDWA ने इन अन्यायपूर्ण गतिविधियों के खिलाफ ज्ञापन तयार किया है, इन गतिविधियों के खिलाफ प्रचार-प्रसार किया है और गिरफ्तार महिलाओं और साथियों की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया है।

स्वास्थ-स्थिति के चलते, सफूरा की जमानत हो गयी है और हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन न्याय की लड़ाई जारी रहेगी

पश्चिम बंगाल मे महातूफान अमफन से भीषण तबाही

- कणिनिका घोष बॉस (मंत्री, पश्चिम बंगाल AIDWA),

- ईशिता मुखर्जी (सदस्य, AIDWA CEC)

एक ऐसे समय में जब बंगाल पहले ही कोरोना महामारी के कारण खतरनाक स्थिति से गुज़र रहा था, 21 मई को अमफ़न महातूफान ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। कम से कम 98 लोग हताहत हो चुके हैं, जिनमे कई महिलाएं भी हैं। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, सुंदरबन सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं। हजारों लोग अपना घर खो चुके हैं। फसलें नष्ट हो गई हैं। कृषि योग्य भूमि पर नमक जमा हो गया है।

'पूरा तबाही का दृश्य था। पेड़ गिर गए,नदियों के बांध टूट गए,चक्रवात के ऊपर से मूसलाधार बारिश आ गई और घरों मे पानी घुस आया,अनेक घरों की छतें गिर गई,अनेक साथियों के घरों मे बाढ़ आ गई। टेलीफोन,इंटरनेट,दूरसंचार की सब सेवाएं अस्त व्यस्त हो गई। 900 से अधिक घर तबाह हो गए। सुंदरबन के जंगल बर्बाद हो गए।' (ईशिता मुखर्जी का तूफान के दौरान मार्मिक वर्णन)

नुकसान की कीमत 13.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बताई जा रही है।

अफसोस की बात है कि मुख्यधारा की मीडिया ने, कुछ अपवादों को छोड़, इस भारी आपदा को बहुत कम समय दिया।

लाक डाउन की सीमाओं को लांघते हुए, AIDWA की राज्य समिति संबंधित जिला समितियों के साथ हर रोज राहत देने का काम कर रही है। राज्य सचिव के साथ राज्य नेतृत्व ने 4 प्रभावित जिलों में दौरा किया है। प्रभावित परिवारों को टारपौलिन, भोजन, नए कपड़े और भोजन वितरित किया जा रहा है।

AIDWA केंद्र ने 5 लाख का राहत फ़ंड जमा करने का आवाहन किया है। केरल की राजी कमेटी 1 लाख भेज चुकी है। फंड एकत्रित करने का काम जारी है।

काली जानें भी अहम (ब्लेक लाईव्ज मैटर)

- सुभाषीनी अली

25 मई 2020 को अमेरिका के मिनियपोलिस (मिनसोटा) मे पुलिस की बर्बरता का शिकार एक बार फिर एक काली नस्ल का व्यक्ति (ब्लैक) बना। ऐसा अक्सर होता है – अमरीका मे 1000 मे एक ब्लैक पुलिस की गोली या हिंसा का शिकार बनता है। इस घटना के बाद, लेकिन, सालों से दबा आक्रोश फूट पड़ा और जार्ज फ्लॉय्ड की इस हत्या के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उनको न पुलिस का डर था और ना ही कोरोना का जबकि उनका देश बुरी तरह से कोरोना की चपेट मे है और करीब एक लाख लोगों की मौत भी इस मर्ज से हो चुकी है।

इसके पहले भी नस्लवादी हिंसा के विरुद्ध आक्रोश प्रदर्शन हुए हैं लेकिन अबकी बार के विरोध मे गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। विरोध के दबाव मे फ्लॉय्ड के शव का पोस्ट मार्ट्म दुबारा करवाया गया और हत्या साबित हुई। उसकी गर्दन को अपने बूट से दबाने वाले पुलिस अधिकारी को हत्या के जुर्म मे गिरफ्तार कर लिया गया है और फ्लॉय्ड के आखरी शब्द 'मैं सांस नहीं ले पा रहा हुँ' अब एक नारा बन गया है जिसे हजारों प्लाइकार्डो पर देखा जा सकता है और प्रदर्शनकारी कंठो से सुना जा सकता है।

अमरीका के कई शहरों मे ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए – इनमे जहां भाग लेने वालों का बहुमत कालों का था, वहीं अन्य लोगों की भी भारी भागीदारी रही। 19 जून को गुलामी के समापन की याद मे हमेशा प्रदर्शन होते हैं लेकिन अबकी साल के प्रदर्शन विशाल ही नहीं बल्कि एक नए संकल्प को दर्शा रहे थे। एक नारा लग रहा था 'न्याय नहीं तो शांति नहीं'। सबसे बड़ा प्रदर्शन तुलसा नामक शहर मे हुआ जिसमे कई दशक पहले काले लोगों का नरसंहार हो चुका है। इसी शहर मे दूसरे ही दिन, करोना संबन्धित तमाम नियमो को दरकिनार रखते हुए, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने चुनाव की पहले रैली भी की।

'काली जानें अहम हैं' के आंदोलन का इस चरण कई कारणो से बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णायक भी हो सकता है। इस दौरान 11 लोग पुलिस की गोलियों और हिंसा के कारण मर चुके हैं, हजारों ने लाठियांऔर आँसू गैस के हमले बर्दाश्त किए हैं। लेकिन इस सबका जैसे कोई असर ही नहीं हुआ और आंदोलन बढ़ता ही गया है। दूसरी ओर इसकी कई उपलब्धियां भी हुई है। पहली बार कालों को मारने वाले पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी संगीन दफाओं मे हो रही है। मार्च मे कोविद एमर्जेंसी विभाग मे काम करने वाली स्वास्थ कर्मी, ब्रेओना टेलर को किसी बेबुनियाद शक के आधार पर पुलिस वालों ने उसके घर मे घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले को आंदोलन ने उठाया और उनके विरोध प्रदर्शन के दौरान ही एक काला , डेविड मकाती, पुलिस की गोली खाकर मर गया। वह बहुत ही जनप्रिय व्यक्ति था जो 'हैम बर्गर' बनाता था। भूखे लोगों को और थके हुए पुलिसवालों को भी मुफ्त मे खिलाता था। इससे लोगों का आक्रोश बेकाबू हो गया और प्रशासन को दोनों मामलो मे दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्यवाही करनी पड रही है।

इस आंदोलन की एक विशेषता यह भी है की इसके संगठनकर्ता स्वयं काले है, कम उम्र के हैं और इनमे बड़ी संख्या मे लड़कियां और नवयुवतियाँ हैं। एक उदाहरण है 15 वर्षीय एम रोज़ स्मिथ जिसने ट्विटर पे 'टीन्स फॉर इक्वालिटी' नाम का संगठन बनाया। उसने अपनी जैसे 6 अन्य लड़कियों के साथ नैशविल, टेनेसी मे एक जुलूस का आह्वान किया जिसमे हजारों लोगों ने भाग लिया! इस तरह के जज़्बे ने इस आंदोलन की सफलता का विश्वास पैदा किया है और उसके प्रति हजारों लोगों को आकर्षित किया है।

इस आंदोलन की अभी तक की बड़ी सफलता यह है की इसके और करोना से निबटने मे असफलता जैसे कुछ अन्य कारणों ने पहली बार ट्रम्प की जनप्रियता को घटाने का काम किया है। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, ट्रम्प ने 20 जून को तुलसा – जो उसका गढ़ है – मे अपनी रैली एक बंद हॉल मे रखी। हॉल पूरा भरा नहीं और हॉल के बाहर जो टी वी लगाए गए थे उनको उतार दिया गया क्योंकि वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था।

ट्रम्प की रैली और आंदोलन के संबंध मे हावर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के निदेशक, आशीष झा, यह कहने के बाद की बंद कमरे मे लोगों को जुटाना कारोना को सबसे अधिक फैलाता है, आगे कहते हैं 'नस्लवाद के अनगिनत सस्वास्थ परिणाम होते हैं....जब लोग इस गहरे संकट को महसूस कर रहे हैं तो उन्हे सार्वजनिक स्वास्थ के कारण घर बैठने की सलाह देना इस सच्चाई को नकारता है....संस्थागत नस्लवाद का सामना करने के लिए इस तरह के आम प्रदर्शन आवश्यक हैं...इतिहास हमे सिखाता है कि नागरिक विरोध से ही राष्ट्र सुधरते हैं। पहले से भी अधिक आज यह आवश्यक हैं।

'काली जानें अहम हैं' का यह आंदोलन निश्चित तौर पर अमरीका की राजनति मे परिवर्तन लाएगा। इससे हमे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे समाज मे भी जाति पर आधारित भेदभाव का बोलबाला है; अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत गहरा रही है; महिलाओं के उत्पीड़न के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अन्याय हर कोने मे पसरा हुआ है। अमरीका मे निर्भीक लड़ने वालों की मिसाल हमे अपने देश मे अन्य के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है।

समीक्षा: "छपाक"

- रीना शाक्य (सहसचिव, मध्य प्रदेश AIDWA)

लक्ष्मी उस वक्त अखबारों की सुर्खियां बन गई थी जब उसके चेहरे पर ऐसिड से अटैक किया गया। ऐसा नहीं है कि ऐसिड अटैक की लक्ष्मी पहली पीड़िता थी,न जाने कितनी लक्ष्मी ऐसिड अटैक की चपेट में आकर अपनी पहचान से लेकर जीवन तक खो चुकी थीं,परन्तु लक्ष्मी के संघर्षों ने समाज में उसे नई पहचान दी।

'छपाक' फिल्म में लक्ष्मी की कहानी को जीवंत करती हुई दीपिका पादुकोण ने मालती के किरदार को बखूबी निभाया है। फिल्म लक्ष्मी के संघर्ष तक सीमित रखना न रहकर, हर एसिड के हमले की शिकार महिला का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी कठिनाई के खिलाफ और पहचान और अस्तित्व की लड़ाई हमले के बाढ़ शुरू होती है।

'छपाक से पहचान ले गया', इस फिल्म के गीत के मार्मिक बोल हैं।

पहचान क्या होती है? सेल्फी के इस दौर में अच्छे से समझ सकते होंगे। लेकिन पहचान उससे कहीं अधिक होती है।

'छपाक' में मालती पर एसिड से हमला करने वाला बशीर खान है जो उससे एकतरफा 'प्रेम' करता है। वह मालती की राजेश से नजदीकी बर्दाश्त नहीं कर पाता और एसिड से हमला कर उस हरे के साथ-साथ उन सपनों को भी कुचलने की कोशिश करता है जो मालती ने देखे थे।

बहादुर मालती के साथ खड़ी होती है एक महिला वकील जो उसके परिवार के सदस्य से अधिक सहयोगी साबित होती है।

लेकिन मालती पर एक और हमला तो राजेश करता है जो उसका चेहरा बिगड़ने पर उसे अपनी प्रेमिका मानने से इंकार कर देता है।

फिल्म मे कई ज्वलंत मुद्दों पर सटीक टिप्पणियाँ कहानी को आगे बढ़ाते हुए की जाती हैं। जब डाक्टर सर्जरी से पहले मालती से पूछता है कि डर तो नहीं लग रहा है तो वह जवाब देती है 'कोर्ट

जितनी नही' और देश मे निर्मम न्याय प्रक्रिया की असलियत बड़े ही प्रभावशाली तरीके से दर्शको के सामने रख देती है।

एक अन्य एसिड पीड़िता अस्पताल मे कहती है कि उसे अपने यहाँ इसलिए इलाज नहीं मिला क्योंकि वह दलित है।

फिल्म का सबसे सटीक डायलाग शाद यह है 'तेज़ाब सबसे पहले हमारे दिमाग मे आता है, उसके बाद बाज़ार मे।' एक महिला की कीमत किस हद तक उसके चेहरे की खूबसूरती के साथ आज भी जुड़ी हुई है!

Facebook: https://www.facebook.com/AIDWA/
Website: http://www.aidwaonline.org